

ग्रामीण जनसंख्या नियंत्रण के उपायों का विश्लेषणात्मक अध्ययन : भारतीय संदर्भ में

रामचन्द्र राणा

शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग, झारखण्ड

सारांश

वर्तमान समय में जनसंख्या की दृष्टि से भारत दुनिया का पहला देश हो गया है। जितनी तेजी से ग्रामीण जनसंख्या बढ़ी है न तो उतनी तीव्र गति से संसाधनों में वृद्धि हुई है और न हीं रोजगार में वृद्धि हुई है। वर्तमान भारत की सबसे प्रमुख समस्या जनसंख्या है। आज गरीबी, बेरोजगारी, प्रदुषण, बढ़ते अपराध आदि समस्याओं के मूल में अत्यधिक जनसंख्या का होना ही है। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे सभी संसाधनों को न्यून कर देता है। अतः यह आवश्यक है कि ग्रामीण जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपायों का मुल्यांकन किया जाए। प्रस्तुत शोध इसी तथ्य पर आधारित है।

शब्द कुंजी – ग्रामीण जनसंख्या, जनगणना वर्ष, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य

परिचय

‘भारत गांव में बसता है’ – यह कथन आज भी उतना ही सत्य है जितना स्वतंत्रता के समय थी। हमारी लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। यह जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या खपत से काफी अधिक है। यही कारण है की आज गांव में गरीबी, बेरोजगारी, श्रम पलायन आदि समस्या चरम पर है। भारत में लगातार कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत घटता जा रहा है यह कोई नई बात नहीं है प्रायः आर्थिक विकास के साथ – साथ ऐसा होता रहा है । लेकिन यह अनुपात अब भी बहुत अधिक है इसे निम्न तालिका द्वारा समझा जा सकता है—

कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत

जनगणना वर्ष	कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत
1891	—
1901	89.2
1911	89.7
1921	88.8
1931	88.0
1941	86.1
1951	82.7
1961	82.0
1971	80.1
1981	76.7
1991	74.3
2001	72.2
2011	68.8

स्रोत— जनगणना— 2011

उपर्युक्त तालिका से साफ स्पष्ट है कि कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत लगातार घटता जा रहा है लेकिन अभी भी जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार 68.8 प्रतिशत है। आज भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गरीबी चारों ओर व्याप्त है। जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि पर जनसंख्या का भार लगातार बढ़ रहा है। जिसका प्रभाव कृषि की उत्पादकता पर भी पड़ा है। कृषि के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर छुपी हुई और मौसमी बेरोजगारी विद्यमान है। कृषि उपज की पूर्ति तथा उसकी मांग में बहुत बड़ा अंतर उत्पन्न हो गया है। बढ़ती जनसंख्या का बोझ ग्रामीण भारत में उपलब्ध पहले से ही सीमित विविध सेवाओं यथा पीने का पानी, स्वास्थ्य, चिकित्सा सेवाएं, आवासीय व्यवस्था आदि पर भी पड़ता है। अनियंत्रित जनसंख्या के कारण अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में लोग गांव

से शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं, जिसके कारण नगरीकरण की नई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जनसंख्या की वृद्धि का प्रभाव सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता पर भी पड़ता है। जनसंख्या के देश में असमान वितरण के कारण राजनैतिक और सामाजिक उपद्रवों को बढ़ावा मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे लोग जिन्हें रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते, वे गैर सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। इससे सभ्य समाज के लिए असुरक्षा और संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः यह आवश्यक है कि ग्रामीण जनसंख्या को कठोरता से नियंत्रित किया जाए।

भारत की ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय कारगर साबित हो सकते हैं—

A. आर्थिक विकास की गति में तीव्रता — ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए यह आवश्यक है कि यदि देश का आर्थिक विकास तीव्र गति से किया जाए तो बढ़ती हुई जनसंख्या से निजात पाई जा सकती है। जनसंख्या वृद्धि की समस्या के उपाय के रूप में आर्थिक विकास को सर्वोत्तम माना जाता है। आर्थिक विकास का तात्पर्य देश के उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय में तीव्र गति से वृद्धि से है। आर्थिक विकास की गति तभी तीव्र होगा जब देश में तेजी से कृषि, उद्योग तथा वाणिज्य व व्यापार का विकास हो। कृषि विकास को तीव्रता प्रदान करने के लिए उत्तम किस्म के बीज, खाद आदि की व्यवस्था के साथ – साथ सिंचाई सुविधाओं का विकास करना होगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास भी करना होगा। कृषि आधारित उद्योग की इसमें अहम भूमिका हो सकती है।

B. आत्म संयम एवं देर से विवाह — ग्रामीण जनसंख्या नियंत्रण के लिए आत्म संयम एवं देर से विवाह काफी महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर मात्थस ने भी इस पर जोर दिया था। यदि लोग विलम्ब से शादी करें अथवा ब्रह्मचर्य का पालन करें तो जन्म दर में कमी लाई जा सकती है। वैसे यह उपाय थोड़ा कठिन एवं अव्यवहारिक जान पड़ता है लेकिन इसका दुष्प्रभाव गर्भ निरोधक दवाओं की तुलना में नगण्य है।

C. **सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सफाई की व्यवस्था** – ग्रामीण जनसंख्या को नियंत्रित करने में सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सफाई की व्यवस्था का अप्रत्यक्ष योगदान रहता है। जब ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे जनसंख्या को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी तब महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार होगा और बाल मृत्युदर घटेगा। बाल मृत्युदर घटने से लोगों को एक बच्चे पर भी भरोसा होगा। स्वास्थ्य तथा सफाई सुविधाओं की उपलब्धता के कारण लोगों की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और वे रोग मुक्त होंगे। इसका सकारात्मक प्रभाव जनसंख्या नियंत्रण पर पड़ेगा।

D. **प्रवास गमन** – ग्रामीण जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए प्रवास गमन का उपाय भी काफी महत्वपूर्ण है। यह प्रवास गमन दो प्रकार का हो सकता है देश के अंदर प्रवास गमन तथा देश के बाहर प्रवास गमन। देश के अंदर जहां घनी आबादी है उन क्षेत्रों से जनसंख्या को विरल आबादी में बसाना देश के अंदर प्रवास गमन कहलाता है। इस कार्य में काफी बाधाएं हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना घर छोड़ दूसरे जगह आसानी से जाना नहीं चाहते। विदेश गमन तो और भी मुस्किल काम है क्योंकि ग्रामीणों को अपना घर और जमीन से अत्यधिक मोह होता है और वह किसी कीमत पर उसे छोड़ना नहीं चाहता। इसके बावजूद भी प्रलोभन और अतिरिक्त सुविधा प्रदान कर प्रवास गमन कराया जा सकता है।

E. **परिवार नियोजन** – परिवार नियोजन का तात्पर्य परिवार में बच्चों के संख्या को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित तथा सीमित करना होता है। इसमें बच्चे संयोग नहीं बल्कि चयन अथवा इच्छा द्वारा शासित होता है। इसमें कृत्रिम तरीके द्वारा जनसंख्या नियंत्रण किया जाता है। गर्भ निरोधक के कृत्रिम साधनों द्वारा संतानोत्पत्ति पर नियंत्रण कर अपने आय के अनुसार लोग अपने परिवार के आकार को नियंत्रित करते हैं। संतति निरोध के निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं –

क. **गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग** – जनसंख्या नियंत्रण के लिए गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग किया जाना बेहद जरूरी है। यह सही है कि लोग इसे अप्राकृतिक मानते हैं तथा कुछ धार्मिक और सामाजिक कारणों से इन्हें

अपनाने में हिचकते हैं, परंतु इनके लाभों का प्रचार कर आम लोगों को इसके प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

ख. शिक्षा का प्रसार – जनसंख्या नियंत्रण के लिए शिक्षा का प्रचार – प्रसार आवश्यक है। संतति निरोध का भी उपयोग शिक्षित व्यक्ति ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि शिक्षित लोगों में परिवार नियोजन की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। अतः शिक्षा के प्रचार – प्रसार द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाया जा सकता है।

ग. प्रचार – परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यह बेहद जरूरी है कि इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार हो। ऐसा देखा जाता है कि भारत में अशिक्षा, निर्धनता, रूढ़ीवादीता इत्यादि के कारण लोग परिवार नियोजन को अपनाने में डरते व हिचकिचाते हैं।

घ. परिवार नियोजन की सुविधाएं – प्रायः ऐसा देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों की पहुंच गर्भ निरोधक संसाधनों तक बहुत कम है। अभी भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां गर्भ निरोधक के न्यूनतम कृत्रिम संसाधन भी उपलब्ध नहीं हैं। इन क्षेत्रों में सरकार द्वारा परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों की सुविधाओं को आम लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाना अति आवश्यक है। इस कार्य के लिए अधिकाधिक संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन क्लीनिकों की स्थापना करना आवश्यक है।

ङ. अनुर्वरीकरण – अनुर्वरीकरण संतति निरोध का सबसे बेहतर तरीका है। यह स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए नसबंदी तथा बंध्याकरण के रूप में किया जाता है। जिस दंपत्ति को दो या उससे अधिक बच्चे हों उनमें से पति या पत्नी को अनुर्वरीकरण अवश्य करा लेना चाहिए। व्यवहार में कुछ लोग इस तरीके को अपनाने में हिचकिचाते हैं क्योंकि एक बार अनुर्वरीकरण करा लेने के पश्चात् पुनः भविष्य में बच्चे देने की संभावना नहीं रहती है। हालांकि सरकार द्वारा इस कार्य के लिए प्रलोभन दिया जाता है जो काफी सराहनीय है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है। गांव में जनसंख्या वृद्धि अधिक होने के कारण वर्तमान में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। साथ ही तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या ग्रामीण संसाधनों को कम कर दे रही है। अतः ग्रामीण जनसंख्या नियंत्रण अति आवश्यक जान पड़ता है। ग्रामीण जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए उपर वर्णित अनेक उपाय सुझाए गए हैं। लेकिन इन सभी उपायों में शिक्षा का प्रचार – प्रसार सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षित व्यक्ति न सिर्फ आय और संसाधनों के अनुकूल परिवार के आकार को नियंत्रित करता है बल्कि लड़का और लड़की में अंतर को भी पाटता है। शिक्षा के प्रचार – प्रसार से ग्रामीण क्षेत्रों में संतति निग्रह के संसाधनों को प्रयोग में जो लोगों के अंदर हिचकिचाहट है वह भी समाप्त हो जाता है। अतः जनसंख्या नियंत्रण के लिए शिक्षा अति आवश्यक है।

संदर्भ सुची

1. वार्षिक रिपोर्ट 2001, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, पृ0सं0 –01
2. धींगरा, ईश्वर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सुल्तान चंद एण्ड सन्स प्रकाशन नई दिल्ली वर्ष 1990, पृ0 सं0 46
3. सिंह, एस.पी., एस. चंद एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, वर्ष 2001, पृ0सं0 282
4. सुमन, डॉ0 एच.एन.पी.एस, भारतीय अर्थव्यवस्था, आलोक भारती प्रकाशन, पटना, वर्ष 2009, पृ0 सं0 57
5. Ahluwalia, Sanjam. 2000. “Controlling births, policing sexualities: A history of birth control in colonial India, 1877-1946”, Ph.D. dissertation, University of Cincinnati.
6. Caldwell, John C. 1998. “Malthus and the less developed world: The pivotal role of India”, *Population and Development Review* 24: 675–696.

7. Cleland J, Bernstein S, Ezeh A, Faundes A, Glasier A, Innis J, et al. *Family planning: The unfinished agenda. Lancet.* 2006;368:1810–27.

8. Landman, Lynn C. 1977a. “Birth control in India: The carrot and the rod?”, *Family Planning Perspectives* 9: 101–105, 108–110.

9. Landman, Lynn C. 1977b. “Indians repudiate coercion, not family planning; will new government support voluntary program?”, *International Family Planning, Digest* 3: 1–5.

10. Ramusack, Barbara N. 1989. “Embattled advocates: The debates on birth control in India, 1920-1940”, *Journal of Women's History* 1: 34–64.

